# होर्मुज संकट से बदला गैस आयात

- अमेरिका बना सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता
- छह महीने में हिस्सेदारी 53 फीसदी

## खाड़ी देशों की पकड़ हुई कमजोर

**नवभारत न्यूज नेटवर्क.**
**नई दिल्ली, 10 सितंबर पश्चिम एशिया में युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का असर अब भारत के रसोई गैस बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है.**

पिछले 6 महीनों में भारत के एलपीजी आयात का नक्शा ही बदल गया है. जो अमेरिका कुछ महीने पहले भारत की एलपीजी जरूरत का छोटा हिस्सा पूरा करता था वह अब सबसे बड़ा करीब 3 गुना बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है. मार्च से अगस्त 2026 के बीच भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 53 फीसदी हो गई. सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान यह सिर्फ 7.9 फीसदी थी. यानी 6 महीने गई. में अमेरिकी हिस्सेदारी करीब 7 गुना हो

कमजोर हुई खाड़ी देशों की पकड़ युद्ध से पहले भारत के एलपीजी आयात में यूएई सबसे बड़ा स्रोत था. सितंबर-फरवरी मैं उसकी हिस्सेदारी 37.8 फीसदी थी, जो मार्च-अगस्त में घटकर 13.4 फीसदी रह गई. कतर की हिस्सेदारी 21.1 से घटकर 5.7. फीसदी और कुवैत की 15.1 से 4.9 फीसदी हो गई. सऊदी अरब की हिस्सेदारी भी 14.1 से घटकर 5.9 फीसदी रह गई.भारत की एलपीजी जरूरत का ई करीब 60 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा होता है. सामान्य स्थिति में भारत के करीब 90 फीसदी एलपीजी आयात पश्चिम एशिया से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आते हैं. युद्ध के कारण इस अहम समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई और भारत को वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़े, केप्लर के शिपिंग आंकड़ों के मुताबिक, मार्च-अगस्त में भारत ने कुल 71.4 लाख टन एलपीजी इसके उलट अमेरिका से आयात 281.1 फीसदी बढ़कर 37.8 लाख आयात की. यह पिछले छह महीनों के मुकाबले 43.1 फीसदी कम है.

> सप्लाई के लिए बढ़ाए विकल्प अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव और समुद्री रास्तों से सप्लाई पर असर पड़ने की स्थिति में भारत के लिए एलपीजी आयात के अलग-अलग स्रोत बनाए रखना अहम हो गया है. अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के साथ-साथ यूएई, कुवैत और कतर से भी सप्लाई बढ़ी. इससे भारत को एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, समुद्री मार्गों की उपलब्धता और एलपीजी की कीमतों के आधार पर आयात का पैटर्न बदल सकता है.

# रोजगार के लिए विदेश जा रहे भारतीय छात्र

## 49% छात्रों ने नौकरी को बताया मुख्य कारण

**नवभारत न्यूज नेटवर्क**
**मुंबई,10 सितंबर देश के विद्यार्थी अब विदेश में पढ़ाई के फैसले को लेकर अधिक नतीजों पर ध्यान दे रहे हैं. करीब आधे छात्र विदेश जाने का मुख्य कारण बेहतर रोजगार के अवसर बता रहे हैं. एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.**

कौशल विकास और कार्यबल विकास कंपनी अपग्रेड की अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार, करीब 49 प्रतिशत भारतीय छात्र-छात्राओं ने विदेश में पढ़ाई करने की प्रमुख वजह बेहतर नौकरी के अवसरों को बताया. इसके अलावा अन्य कारण शिक्षा की गुणवत्ता, स्थायी रूप से वहीं बसने की इच्छा और जीवनशैली है. रिपोर्ट में कहा गया है कि

अपग्रेड स्टडी अब्रॉड के विश्वविद्यालय साझेदारी मामलों के उपाध्यक्ष प्रनीत सिंह ने कहा विदेश में पढ़ाई के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है. भारतीय छात्र अब भविष्य में रोजगार मिलने की संभावना, करियर में आगे बढ़ने के अवसर और कम खर्च को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं. यूरोप की बढ़ती लोकप्रियता छात्रों की इसी बदलती सोच को बताती है. भारतीय छात्र अब केवल प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम के आधार पर विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं. वे पढ़ाई पर होने वाले खर्च के मुकाबले मिलने वाले लाभ, रोजगार के अवसर और लंबे समय में करियर की संभावनाओं को अधिक महत्व दे रहे हैं.

> जनवरी, 2025 से जून, 2026 के बीच सलाह लेने वाले 53,800 छात्रों से मिली जानकारी पर आधारित है. इनमें 65 .8 प्रतिशत नए स्नातक थे, जबकि करीब 60 प्रतिशत छात्र मझोले और छोटे शहरों के थे. रिपोर्ट में शामिल ज्यादातर छात्र अपने करियर की शुरुआत में थे और हाल ही में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी. इनमें 65 .8 प्रतिशत नए स्नातक थे, जबकि करीब 60 प्रतिशत छात्र दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों से थे.

# कैमरा और एआई की ताकत के साथ आए आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स

- नया ए20 प्रो चिप, पहली बार वैरिएबल अपर्चर वाला 48 मेगा पिक्सल कैमरा

**नवभारत न्यूज नेटवर्क**
**नयी दिल्ली, 10 सितंबर कैलिफोर्निया एप्पल ने अपनी नई आईफोन 18 प्रो श्रृंखला पेश कर दी है. कंपनी ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स में कैमरा, प्रदर्शन, बैटरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर खास जोर दिया है.**

दोनों मॉडल नए ए20 प्रो चिप, आईओएस 27 और नए रूप वाले डायनेमिक आइलैंड के साथ आए हैं. भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए रखी गई है. दोनों फोन के लिए 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे, जबकि बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी.आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स में पहली बार 48 मेगापिक्सल के मुख्य कैमरे के साथ वैरिएबल अपर्चर दिया गया है. छह ब्लेड वाला यह कैमरा चार अलग-अलग अपर्चर स्तरों पर काम कर सकता है और रोशनी तथा तस्वीर की गहराई के अनुसार इसे अपने आप भी बदला जा सकता है. कंपनी ने कैमरे में पेशेवर नियंत्रण भी जोड़े हैं, जिनसे उपयोगकर्ता शटर गति और सफेद संतुलन जैसे विकल्पों को नियंत्रित कर सकेंगे. वीडियो के लिए भी कई नए फीचर दिए गए हैं. दोनों फोन में ए20 प्रो चिप दिया गया है, जो 2 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है.

> **वैरिएबल अपर्चर कैमरा-** पहली बार आईफोन में मुख्य कैमरे का अपर्चर बदला जा सकेगा. छह ब्लेड वाला सिस्टम चार अपर्चर स्तरों पर काम करेगा.
> **48 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा** - बेहतर रोशनी, गहराई और तस्वीरों पर ज्यादा नियंत्रण.
> **ए20 प्रो चिप** - 2 नैनोमीटर तकनीक वाली नई चिप, ग्राफिक्स प्रदर्शन 40% तक तेज.
> **दोगुनी एआई क्षमता-** नया न्यूरल इंजन एआई से जुड़े कामों के लिए पिछली पीढ़ी से दोगुनी क्षमता देता है.
> **नया डायनेमिक आइलैंड-** आकार छोटा किया गया है, लेकिन एक साथ ज्यादा जानकारी और तीन लाइव गतिविधियां दिखा सकता है.
> **3,000 निट्स चमक** - तेज धूप में भी स्क्रीन ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने का दावा.
> **बेहतर बैटरी-** प्रो में 36 घंटे और प्रो मैक्स में 45 घंटे तक वीडियो चलाने का दावा.
> **तेज चार्जिंग-** प्रो मॉडल करीब 15 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है.

# रेरा का कमजोर अमल, 27 .6 लाख खरीदारों का पैसा अटका

**नवभारत न्यूज नेटवर्क.**
**नई दिल्ली,10 सितंबर.** घर खरीदारों के संगठन एफपीसीई ने रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रेरा कानून को राज्यों में ठीक से लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि देशभर में करीब 27.6 लाख घर खरीदार आवासीय परियोजनाओं में देरी केएफपीसीई के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा, रेरा एक कानून के रूप में विफल नहीं हुआ है, इसके क्रियान्वयन में कमी रही है. और जब क्रियान्वयन कमजोर पड़ता है, तो मजबूत से मजबूत कानून भी व्यवहार में विफल हो जाता है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि करीब 27.6 लाख घर खरीदार परिवारों की रकम बिल्डरों के पास फंसी हुई है.

# टाटा बनाएगा चीन को चुनौती देने वाला जोरावर टैंक

- 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार
- महिंद्रा भी तैयार करेगा लाइट टैंक प्रोटोटाइप

**नवभारत न्यूज नेटवर्क.**
**नई दिल्ली, 10 सितंबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी नापाक हरकतों से बाज न आने वाले चीन को अब मुहतोड़ जवाब मिलने वाला है. भारतीय सेना के 20,000 करोड़ रुपये के सबसे बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स में से एक 'प्रोजेक्ट जोरावर' को रफ्तार मिल गई है.**

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए खास लाइट टैंक बनाए जाएंगे. ताजा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे भरोसेमंद औद्योगिक घराने टाटा समूह ने इस भारी-भरकम प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाकर बाजी मार लगी है. वहीं आनंद महिंद्रा की अगुवाई वाली महिंद्रा भी इस प्रोजेक्ट की हिस्सा बनेगी और टैंक का प्रोटोटाइप तैयार करेगी. 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख और एलएसी के कई ऊंचे इलाकों में अपने हल्के टैंक तैनात कर दिए हैं.

### भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी

टाटा और महिंद्रा जैसी स्वदेशी कंपनियों के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से न केवल 'मेक इन इंडिया' को बूस्ट मिलेगा बल्कि एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी.विमानों के जरिए आसानी से एयरलिफ्ट करके कम समय में सीमा पर किसी भी ऊंचाई वाले इलाके में तैनात किया जा सकेगा

# जीएसटी की रफ्तार पर सवाल सीबीआईसी का तीखा जवाब

- अगस्त में जीएसटी संग्रह पहली बार 2 लाख करोड़ पार
- सरकार ने 14 .8% वृद्धि का दावा किया

**नवभारत न्यूज नेटवर्क.**
**नई दिल्ली, 10 सितंबर अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने और सकल जीएसटी में 14.8 प्रतिशत वृद्धि के दावे पर पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने सवाल उठाए हैं.**

गर्ग ने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्ष 2025-26 के क्षतिपूर्ति उपकर को गणना से बाहर कर जीएसटी वृद्धि की तस्वीर को बेहतर दिखाया है. उनके मुताबिक, उपकर को भी शामिल करने पर पांच महीने की सकल जीएसटी वृद्धि महज 4.08 प्रतिशत और शुद्ध वृद्धि 1.30 प्रतिशत रह जाती है.

गर्ग के सवालों के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया. बोर्ड ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर को गणना से बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह कर अब वसूला ही नहीं जा रहा है. जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर खत्म करने का फैसला किया था. तंबाकू उत्पादों पर भी इसे 1 फरवरी 2026 से समाप्त कर दिया गया.सीबीआईसी के अनुसार, नवंबर 2025 से जारी जीएसटी राजस्व आंकड़ों में क्षतिपूर्ति उपकर को अलग से दिखाया गया है.

# चीनी की बढ़ेगी आपूर्ति, 2 .5 लाख टन बिक्री

**नवभारत न्यूज नेटवर्क**
**नई दिल्ली, 10 सितंबर.चीनी की कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिशों के बीच देश की चीनी रिफाइनरियां घरेलू बाजार में करीब 2.5 लाख टन सफेद चीनी बेचने की योजना बना रही हैं. उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.**

रेणुका शुगर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुशील कुमार ने कहा कि हमने घरेलू बाजार में चीनी की

मिल स्तर पर कीमत फिलहाल करीब 43-44 रुपये प्रति किलोग्राम है जो आयातित चीनी की करीब 50 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुमानित लागत से कम है.

# अदाणी एंटरप्राइजेज में 25 प्रतिशत तेजी की उम्मीद

## अदाणी एयरपोर्ट्स की 9,825 करोड़ की पूंजी जुटाने की घोषणा

**नवभारत न्यूज नेटवर्क**
**नई दिल्ली, 10 सितंबर. अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में आगे तेजी की उम्मीद जताई गई है. प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों एमओएफएसएल और जेफरीज ने कंपनी के शेयर पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखते हुए ऊंचे लक्ष्य मूल्य दिए हैं. एमओएफएसएल ने शेयर का लक्ष्य 3,880 रुपए रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 25 प्रतिशत तेजी की संभावना दर्शाता है.**

वहीं जेफरीज ने 3,830 रुपए का लक्ष्य देते हुए खरीदारी की सलाह दी है.एमओएफएसएल के मुताबिक अदाणी एंटरप्राइजेज की मजबूत बाजार स्थिति, कारोबार का विविध स्वरूप, बड़े स्तर पर परिचालन और नए कारोबार खड़े करने की क्षमता कंपनी के पक्ष में है. ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के प्रमुख कारोबारों में आगे भी पूंजी जुटाने और रणनीतिक निवेश की गुंजाइश बनी हुई है.

इससे समूह की बड़ी विस्तार योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है.

> एमओएफएसएल ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 के बीच अदाणी एंटरप्राइजेज के समेकित राजस्व में करीब 22 प्रतिशत, परिचालन लाभ में 29 प्रतिशत और शुद्ध लाभ में 82 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी के नए कारोबारों का विस्तार और मौजूदा व्यवसायों का बेहतर प्रदर्शन भविष्य में मूल्य बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं.

## समाचार विशेष

# पंजाब में अकाली दल की मुश्किलें

## जनाधार घटा, नई पंथक राजनीति की ओर वोट मुड़ा

**जालंधर, 10 सितंबर. पंजाब में अकाली दल के सामने पंथक वोट बैंक को एकजुट करने की बड़ी चुनौती है. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मत प्रतिशत घटकर महज 13.42 फीसदी रह गया, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल तीन सीटें मिली थीं.**

यह गिरावट 2017 के बाद से लगातार जारी है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में उसकी पकड़ कमजोर हुई है. पार्टी को अब अपने बिखरे हुए राजनीतिक आधार को फिर से संगठित करना होगा. अकाली दल को 2014 में 26.30 फीसदी और

2019 में 27.45 फीसदी वोट मिले थे लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 13.42 फीसदी पर आ गया जिससे पार्टी सिर्फ बठिंडा लोकसभा सीट जीत सकी. इस बीच, सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) को 2024 में करीब 3.82 फीसदी वोट मिले. निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा की जीत ने भी पंथक वोटों के बिखराव को दर्शाया. इन नतीजों से स्पष्ट है कि अकाली दल से दूर हुआ पंथक वोट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भाजपा के पास पूरी तरह नहीं गया बल्कि इसका एक हिस्सा नई पंथक राजनीति की ओर मुड़ गया है. सुखबीर बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल अपने पुराने संगठन को बचाने का प्रयास कर रहा है. वहीं पुनर्सुरजीत धड़ा और वारिस पंजाब दे जैसे समूह भी अपनी पहचान बना रहे हैं. यह स्थिति अकाली राजनीति के सामने विरोधी दलों से भी बड़ी चुनौती पेश करती है.

### कई हिस्सों में बंट गया वोट बैंक

अकाली दल का वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसका एक बड़ा हिस्सा अब अलग-अलग पंथिक राजनीतिक धाराओं में बंट गया है. सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) को 2024 में 3 .82 फीसदी वोट मिले. निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा की जीत भी इसी बदलाव का संकेत है. यह दर्शाता है कि पंथिक वोट राष्ट्रीय दलों के बजाय नई पंथक राजनीति की ओर भी गया है.

# बिहार में एनडीए को चाहिए एक जीत

**पटना, 10 सितंबर. बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीट के साथ प्रचंड जीत मिली थी. लेकिन उसके बाद भोजपुर शाहाबाद की विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ जदयू के उम्मीदवार को राजद ने हरा दिया.**

कहा गया कि भाजपा ने सहयोग नहीं किया है. उसके बाद पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो वहां भाजपा का उम्मीदवार हार गया.

भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट नहीं बचा सकी. तभी अब कहा जा रहा है कि राज्य की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले विधान परिषद चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत चाहिए. हालांकि हर सीट पर समीकरण उलझा हुआ है और एनडीए के लिए मुश्किल है. उससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में घमासान शुरू हो गया है. पटना की स्नातक सीट से लगातार तीन बार चुनाव जीत रहे नीरज कुमार इस बार भी चुनाव लड़ेंगे लेकिन जनता दल यू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने उनको हराने की घोषणा कर दी है.

# राजनीति में एंट्री को तैयार बृजभूषण सिंह की बेटी

**लखनऊ. उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह ने राजनीति में आने की इच्छा जताई है, जिसके बाद यूपी की सियासत में कयासों का दौर शुरू हो गया है. बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शालिनी सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी और कहा कि वो अब पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होने का मन बना चुकी है.**

शालिनी सिंह बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने राजनीति में कदम रखने की तैयारी के संकेत दिए, उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में पहचान किसी पार्टी या टिकट से नहीं, बल्कि सही नेतृत्व और जनता के लिए किए कामों से बनती है, अगर किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहता है, तो मैं चुनावी मैदान पर उतरने के लिए तैयार हूं. शालिनी सिंह ने इस दौरान अपने समाज के लिए किए जाने वाले कामों को भी गिनाया और उन्होंने कहा कि वो पिछले 15 सालों से नोएडा सामाजिक क्षेत्र के कार्यों में सक्रिय है, इसलिए वे अब भारतीय राजनीति में उतरना चाहती है. उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी या विपक्ष में भरोसा नहीं करती बल्कि सही मुद्दों पर आवाज़ उठाने में यकीन करती है. जब भी समाज से जुड़े अहम मुद्दे होते हैं वो खुलकर उन पर अपनी राय रखती हैं चाहे वो यूजीसी का मामला हो या कुछ और.

## विशेष | झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी की शुरू हुई तलाश

# झारखंड में विरासत संभालने की जद्दोजहद

**रांची, 10 सितंबर. सियासत में भावनाओं का कोई लंबा विराम होता है. नेता के जाने का गम अभी ताजा ही होता है कि राजनीति के अगले सवाल कुलबुलाने लगते हैं. कहते हैं कि वक्त बड़ा बेरहम होता है. कल तक जिस नाम के साथ चुनावी रणनीति बनती थी, कार्यकर्ताओं की बैठकें होती थीं और गिरिडीह के विकास की बातें होती थीं, आज वही नाम सिर्फ याद बन गया.**

यह नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कद्दावर नेता और सेकेंड टू सीएम सुदिव्य कुमार सोनू है. इस समय सुदिव्य सोनू की अंतिम विदाई के बाद पूरा शहर शोक में डूबा है, मगर सियासत के पन्ने तेजी से पलटने लगे हैं. शहर के फिजां में तैरने लगा है, कौन होगा सुदिव्य सोनू की विरासत? उनकी राजनीतिक विरासत का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? इन सवालों पर सवाल अब धीरे-धीरे चर्चा होने लगी है.

सुदिव्य कुमार सोनू का अचानक जाना सिर्फ एक परिवार, एक पार्टी या एक विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा सदमा नहीं है, बल्कि गिरिडीह की राजनीति में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ है, जिसे भरना आसान नहीं होगा. करीब तीन दशक तक झामुमो से जुड़े रहे सुदिव्य ने संगठन की राजनीति से लेकर चुनावी मैदान और फिर सरकार के शीर्ष स्तर तक अपनी जगह बनाई थी. 2019 में पहली बार गिरिडीह से विधायक बने और 2024 में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की. इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी तक पहुंचे. सुदिव्य के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि गिरिडीह विधानसभा सीट पर अगला चेहरा कौन होगा? असली सवाल यह है कि गिरिडीह में सुदिव्य ने जो राजनीतिक जमीन तैयार की, उसे आगे कौन संभालेगा? उनके समर्थकों और झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच स्वाभाविक रूप से यह चर्चा है कि पार्टी अब किस चेहरे पर भरोसा करेगी? सुदिव्य की वर्षों की मेहनत से तैयार संगठन, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और जनता के बीच उनकी व्यक्तिगत पकड़ किसी एक दिन में किसी दूसरे नेता को नहीं मिल सकती.

**झामुमो के सामने भी बड़ी चुनौती**

सुदिव्य कुमार सोनू सिर्फ गिरिडीह के विधायक नहीं थे. झामुमो संगठन में उनकी लंबी पारी रही थी. 1989 में पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियां संभालीं और 2003 में गिरिडीह जिला अध्यक्ष भी बने.

### क्या परिवार से निकलेगा नया चेहरा?

सियासी गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि क्या सुदिव्य कुमार सोनू का परिवार उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा? उनकी पत्नी श्वेता शर्मा के नाम को लेकर भी चर्चाएं सामने आने लगी हैं. हालांकि, अभी इसे लेकर न तो कोई औपचारिक फैसला हुआ है और न ही परिवार की ओर से कोई स्पष्ट राजनीतिक घोषणा सामने आई है. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय राजनीति में यह कोई नया उदाहरण नहीं होगा. कई बार किसी लोकप्रिय नेता के निधन के बाद परिवार का कोई सदस्य राजनीति में उतरकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाता रहा है.

### सियासत में एक्टिव रहा पूरा परिवार

शालिनी सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं. उनके पिता भी कैसरगंज सीट से छह बार के सांसद रह चुके हैं. उनके दो भाई पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और मां केतकी देवी भी सांसद रह चुकी हैं. बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर सीट से विधायक है और छोटे भाई कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं. पिता पक्ष की तरह ही शालिनी सिंह का ससुराल पक्ष भी सियासत में काफी सक्रिय रहा है. शालिनी की शादी बिहार के आरा के पूर्व सांसद अजीत सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के इकलौते बेटे विशाल से हुई है. शालिनी अपने परिवार के साथ नोएडा में रहती हैं और आरएसएस की महिला शाखा से भी जुड़ी हुई हैं. बैठक में गठबंधन को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई.